दिल्ली में विकलांगों का संस्थान

193. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री नारायण चौबे :

क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में विक्लांगों के संस्थान के लिए प्रति वर्ष अनुदान की कितनी राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है ;

(ख) क्या इस संस्थान का प्रबन्ध असन्तोषजनक है; और

(ग) यदि हां, तो इस के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) (क) : नई दिल्ली में विक्लांगों के संस्थान के लिए वर्ष 1980-81 हेतु 23,80,000 रुपए का बजट प्रावधान है ।

(ख) और (ग). हाल में संस्थान के प्रबन्ध में कुछ कमियां सरकार के नोटिस में आई थीं । इन के बाद इन को दूर करने के लिए और इस के कार्य को तीव्र करने हेतु कार्यवाही शुरू की गई । इन में निदेशक का परिवर्तन तथा कार्यशाला के प्रबन्ध के तकनीकी पहलुओं सहित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर की ऐसोसिएशन का परिवर्तन शामिल है । फिर भी, इन कार्यवाहियों को दो रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है जिन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. 1980 की सिविल रिट याचिका संख्या 1128 श्री रघुनन्दन प्रसाद, आवेदक
बनाम

भारत सरकार—प्रतिवादी

2. 1980 की सिविल रिट याचिका संख्या 1301 श्री बाल किशन तथा अन्य—आवेदक—बनाम

भारत सरकार—प्रतिवादी ।

पहली रिट याचिका प्रवेश के लिए अभी भी उच्च न्यायालय में अनिर्णीत पड़ी हुई है । जहां तक दूसरी याचिका का सम्बन्ध है उच्च न्यायालय ने प्रवेश के लिए याचिका पर पहले ही सुनवाई कर ली है लेकिन इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा पास किए गए आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

Employment of Rural Educated unemployed under National Rural Employment Programme

*194. SHRI JITENDRA PRASAD. Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

(a) whether the 'National Rural Employment Programme' is not catering to the employment requirements of rural educated unemployed *i.e.* Matriculates and Graduates because of their academic and other background which as a matter of fact render them unfit for manual labour;

(b) if so, whether Government contemplate to devise alternative measures for providing employment to educated rural unemployed or amend the existing National Rural Employment Programme so as to ensure participation of rural educated youths in the programme by providing them with supervisory or ministerial assignments in this programme; and

(c) if not, the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI BALESHWAR RAM): (a) to (c). The